रुपये की राशि से बहुत कम राशि राहत के रूप में दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा दिए गए अल्पावधिक और सावधि ऋणों पर 2.10.1989 तक की अतिदेय राशियों के लिए पात्र ऋणकर्ताओं को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण राहत प्रदान की गई थी। सहकारी समितियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदान की गई राहत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	उन हिताधिकारियों की संख्या जिन्हें राहत प्रदान की गई	ऋण राहत की राशि
राज्य सहकारी बैंक	33.84 लाख	545.95 करोड़ रुपए
राज्य भूमि विकास बैंक	3.03 लाख	101.33 करोड़ रुपए

किसी ऋणकर्ता की अतिदेय राशि को ध्यान में रखते हुए राहत की निश्चित राशि अलग-अलग ऋणकर्ता के मामले में अलग-अलग तथा अलग-अलग बैंक की अलग-अलग होगी और इस प्रकार किसी एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की तुलना में कम राहत प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

यह योजना 31.3.1991 को समाप्त हो गई है।

Entrusting implementation of R.LiD.Cs. to N.P.T.C.

*342. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to entrust the implementation of all future unified Regional Load Despatch Centres in the country to the National Power Transmission Corporation;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) what are the reasons for World Bank's concern with N.P.T.C's performance; and

(d) what is the total unutilised aid in the power sector?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Government has decided to entrust only the construction of future unified load despatch & communication facilities in the country to National Power Transmission Corporation in consultation with the concerned States.

(b) The work relating to the construction of future unified Load Despatch and Communication facilities in the country has been included in the functions of NPTC from the point of view of ensuring compatibility of equipment / system at the regional and State levels and better coordination in implementation of the entire scheme.

(c) World Bank's concern emanates from the financial support extended for the transmission projects presently managed by the NPTC.

(d) The unutilised amount of World Bank assistance for power projects is US $ 3739.527 million (upto Feb., 1992).

देश में पवन से बिजली का उत्पादन

*343. **श्री रणजीत सिंह:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "इनसेन्टिव्ज फार इन्वेस्टमेन्ट इन विंड पावर जेनेरेशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में पवन से बिजली के उत्पादन की कुल कितनी क्षमता है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षमता में वृद्धि करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी हां।

(ख) 31.12.1991 तक 38.3 मे०वा०. की कुल क्षमता प्रारंभ की गई और इसे संबंधित राज्य ग्रिडों से जोड़ा गया। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में लगभग 25 मे०वा० की कुल क्षमता के पवन विद्युत जनित्र स्थापित किए जा रहे हैं।